RAVINDER KUMAR RAWAL u V.K. SOOD AND OTHERS #
(A.N. Jindal, J.)

एमएम कुमार और एएन जिंदल से पहले जे.जे.

रविंदर कुमार *रावल, अपीलकर्ता*

बनाम

वीके सूद और अन्य, - *प्रतिवादी*

एलपीएएनओ. 2010 का 68 और
एलपीएएनओ। 2010 का 1617

23 मई 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226--हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1978-आरआईएस। 71 और 76-नगर परिषद के लिए चुनाव-पार्षद चुने गए-परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव-अपीलकर्ता को सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया-प्रतिवादी 1-आरआई द्वारा इसे चुनौती दी गई। 1978 के नियमों के 71 में मतपत्र पर 'हां' या 'नहीं' लिखने की आवश्यकता है और रिटर्निंग अधिकारी को सदस्यों से मतपत्र पर 'एक्स' का चिह्न लगाने की आवश्यकता है - चाहे वह आरआई का उल्लंघन करता हो। 1978 के 71 नियम और क्या इसका उल्लंघन चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित करता है - माना जाता है, नहीं - 'एक्स' के निशान से वोट देने वाले किसी भी मतदाता पर कोई पूर्वाग्रह नहीं - प्रतिवादी नंबर 1 मतपत्र स्वीकार करता है, किसी विशेष उम्मीदवार के लिए इसका समर्थन करता है, इसके बिना हार स्वीकार करता है गोपनीयता के किसी भी उल्लंघन की ओर इशारा करते हुए - गोपनीयता के उल्लंघन का कोई कृत्य साबित नहीं हुआ - अपील की अनुमति दी गई, एकल न्यायाधीश के फैसले के साथ-साथ चुनाव याचिका को भी रद्द कर दिया गया।

माना गया कि गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका या आशंका के आधार पर किसी भी चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। गोपनीयता के उल्लंघन का ऐसा कोई कृत्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित या सिद्ध नहीं किया गया है। यदि हम अपनी याचिका में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निर्धारित दलीलों पर गौर करें, तो खुलासा करने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्या सूची तैयार करने, मतपत्र जारी करने और मतदान के समय, कोई मतपत्र लीक हुआ था, जिसने प्रभावित किया था , निर्वाचक से प्रभावित, पूर्वाग्रहित होकर उसने जो सोचा था उससे भिन्न तरीके से अपना वोट डाला। कोई भी मतदाता यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि गोपनीयता भंग होने के कारण ऐसे किसी दबाव के कारण उसे अपना मन बदलना पड़ा या किसी उम्मीदवार ने उसे किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर किया। केवल अस्पष्ट दलीलें हैं कि क्रमांक संख्या अंकित होने से मतदाताओं को यह महसूस हुआ होगा कि उनके मतपत्र

जांच के लिए खुले थे और प्रतिशोध के डर से, उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया होगा।

(पैरा 29)

आगे माना गया कि 1973 के अधिनियम की धारा 275 और 275-ए गोपनीयता बनाए रखने का उल्लेख करती है। 951 के अधिनियम की धारा 128 और 1961 के नियमों के नियम 39 उपरोक्त प्रावधानों के लिए आवश्यक हैं। इन धाराओं में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि चुनाव कराते समय चुनाव में लगे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मतपत्र की गोपनीयता किसी को नहीं बताएंगे (कानून के तहत आवश्यक को छोड़कर) और यदि वे जानबूझकर गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं, तो यह माना जाएगा चुनावी अपराध के रूप में दोनों अधिनियमों के तहत जुर्माना या कारावास से दंडनीय है। मतदान की गोपनीयता या मतपत्र की गोपनीयता का अर्थ यह तथ्य है कि किसी चुनाव में एक से अधिक प्रतियोगियों में से किसी मतदाता ने अपना वोट किसे दिया है, इसकी जानकारी जनता को नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि अधिनियम की धारा 94 एक मतदाता को यह विशेषाधिकार देती है कि वह यह गवाही देने से इनकार कर सके कि उसने किसे अपना मत डाला है, और धारा 128 व्यक्तियों को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने से रोकती है। इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य से, यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी स्तर या समय पर गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, जो कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली भौतिक अनियमितता थी। किसी भी मामले में, यह प्रतिवादी नंबर 1 का मामला नहीं है जिसने मतपत्र पर सीरियल नंबर मुद्रित किया या मतदाताओं की अलग शीट/रजिस्टर पर सीरियल नंबर डाला या कहा कि 'दृश्य प्रतिनिधित्व' का गठन किया गया है जिसके द्वारा मतदाता की पहचान की जा सकती है और, इसलिए, चुनाव रद्द करने को उचित ठहराने या उचित ठहराने में गोपनीयता का उल्लंघन हुआ।

(पैरा 31)

इसके अलावा, यह माना गया कि कार्रवाई के पूर्ण कारण के अभाव में चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य नहीं देने से चुनाव के नतीजे कैसे प्रभावित हुए हैं और वह भी यह नहीं बताने से कि याचिकाकर्ता के लिए किसने मतदान किया है इस आशंका या प्रत्याशित गोपनीयता के उल्लंघन के परिणाम के आधार पर अपीलकर्ता का चुनाव शून्य था, चुनाव याचिका में कोई विचारणीय मुद्दे का खुलासा नहीं किया गया। यह अच्छी तरह से तय है कि भले ही अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन/गैर-अनुपालन हो, हालांकि वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक कि ऐसी कोई याचिका दायर करने वाला पक्ष इसे साबित करने में सफल नहीं हो जाता। इसके उल्लंघन पर, निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है, निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा, यह माना गया कि कानून, नियमों और प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक रूप से आयोजित चुनाव में मतपत्र के माध्यम से व्यक्त की गई लोगों की इच्छा का गला घोंटने के लिए

अत्यधिक तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पर्याप्त ढांचे को परेशान किए बिना नियम का एक मामूली विचलन एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी आधिकारिक कार्य को अवैध नहीं बनाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया शून्य हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय और विकासात्मक गतिविधियां रुक जाती हैं, और निर्वाचित मशीनरी बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। इस प्रकार, प्रक्रियात्मक प्रावधानों को थोड़ा भी नजरअंदाज करने से पूरी प्रक्रिया शायद ही शून्य हो सकती है, जब तक कि संविधान के मौलिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो। याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी संख्या 1) ने मतपत्र को स्वीकार करने, किसी विशेष उम्मीदवार के लिए इसका समर्थन करने, उस समय की कार्यवाही को चुनौती दिए बिना और गोपनीयता के ऐसे उल्लंघन को इंगित किए बिना हार स्वीकार कर ली, जो कि भौतिक रूप से हो सकती है। चुनाव के नतीजे को प्रभावित किया, चुनाव को चुनौती दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने मंसूबे में विफल रहे हैं. चुनाव न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायालय दोनों ने मूल मुद्दों को छुआ है और चुनाव परिणाम में गड़बड़ी की है, जबकि यह मानते हुए कि चुनाव के परिणामस्वरूप गोपनीयता का अपेक्षित उल्लंघन हुआ, यह अवैधता की श्रेणी में आता है। लेकिन ट्रिब्यूनल के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि क्या गोपनीयता का उल्लंघन चुनाव को रद्द करने का आधार था और क्या गोपनीयता का कोई उल्लंघन हुआ था और क्या इस संबंध में पर्याप्त दलीलें थीं। इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि ट्रिब्यूनल के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने भी संभावित तरीके से साक्ष्य और कानून की सराहना करने में गलती की है। परिणामस्वरूप, निर्णयों के माध्यम से उनके द्वारा दिये गये निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले में मूल मुद्दों को नहीं छुआ गया है, जो प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं से प्रभावित हैं, जो बहुमत की आवाज को चुप कराने के लिए शायद ही पर्याप्त हैं। इसलिए, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया है।

(पैरा 34)

संजय बंसल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित झांजी और आशा चौहान की सहायता से, *अपीलकर्ता के वकील (2010 के एलपीए संख्या 68 में)*

सुखबीर सिंह मत्तेवाल, एडवोकेट/डॉ *प्रतिवादी नंबर 1.*
अमन चौधरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

एएन जिंदल, जे.

(1) यह निर्णय दो अपीलों का निपटारा करेगा। एलपीएएनओ. रविंदर कुमार रावल द्वारा दायर 2010 का 68 और 2010 का एक अन्य एलपीए नंबर 1617 उपायुक्त, पंचकुला और एक अन्य द्वारा दायर किया गया, दोनों इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित 8 जनवरी, 2010 के सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुए। हालाँकि, दोनों अपीलों पर निर्णय देने के लिए तथ्य 2010 के एलपीए संख्या 68 से लिए गए हैं।

(2) नगर परिषद, पंचकुला के अध्यक्ष पद के लिए एक असफल उम्मीदवार द्वारा चुनाव को चुनौती देने के लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (यहां '1973 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित पदानुक्रम ऑफरिब्यूनल के माध्यम से यात्रा करने के बाद, फैसला सुनाया गया। चुनाव न्यायाधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी नंबर 1-वीके सूद के पक्ष में दर्ज किया गया है। नतीजतन, अपीलकर्ता - उम्मीदवार रविंदर कुमार रावल (यहां 'अपीलकर्ता* के रूप में संदर्भित) भी इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष हार गए। उनका चुनाव निम्नलिखित आधारों पर रद्द कर दिया गया:-

1. तैयारी में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया
मतदाता सूची और मतपत्रों पर क्रम संख्या अंकित करना गोपनीयता का उल्लंघन है, जिसे चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाली भौतिक अनियमितता माना जाता है;

2. रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदाताओं को मतपत्र पर 'X' अंकित करने का निर्देश देते हुए नियमों का उल्लंघन किया, जो कि हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 (यहां '1978 के नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 71 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए, यह अवैध रूप से वोट प्राप्त करने के समान है, जो कि अनुमति योग्य नहीं है और 1978 के नियमों के नियम 85 (एल) (डी) (iii) के तहत प्रदान किए गए अनुसार चुनाव को रद्द करने का आधार है।

3.) हमारे सामने निर्धारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

(1) क्या 1978 के नियमों का नियम 71 निर्देशिका है या अनिवार्य है
प्रकृति में और क्या इसका उल्लंघन चुनाव के परिणाम को प्रभावित करता है?

(11) क्या निर्वाचकों के नाम, उनके वार्ड नंबर और हस्ताक्षर के साथ-साथ मतपत्रों की क्रम संख्या (जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखा जाना है) वाले कागज की अलग शीट तैयार करना चुनाव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाली गोपनीयता का उल्लंघन है? परिणाम ?

(111) क्या चुनाव याचिका 1978 के नियमों के नियम 76 के अनुरूप है और इस प्रकार, कार्रवाई के कारण के अभाव में चुनाव याचिका खराब थी।

(4) उपरोक्त बातें पक्षों की दलीलों में बताए गए तथ्यों से उत्पन्न हुई हैं। 31 नगर पार्षदों को चुनने के लिए नगर परिषद, पंचकुला का चुनाव 30 मार्च, 2008 को हुआ। श्री रविंदर कुमार रावल-अपीलकर्ता को वार्ड नंबर 14 से निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि श्री वीके सूद-प्रतिवादी नंबर 1 को वार्ड नंबर 4 से निर्वाचित घोषित किया गया। पार्टी-वार विजयी उम्मीदवारों की कुल संख्या इस प्रकार है: कांग्रेस—9; बीजेपी-8; इनेलो-6 और निर्दलीय-8.

(5) परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक 14 मई, 2008 को बुलाई गई थी, जिसमें अपीलकर्ता रविंदर कुमार रावल (कांग्रेस उम्मीदवार), प्रतिवादी नंबर 1, वीके सूद (एक भाजपा उम्मीदवार) और एक वीके कपूर (एक इनेलो उम्मीदवार) ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी गयी. किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई और यह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। गिनती करने पर, अपीलकर्ता (कांग्रेस से) को 13 वोट हासिल करके निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि प्रतिवादी नंबर 1, वीके सूद (भाजपा से) को 10 वोट और वीके कपूर (आईएनएलडी से) को 9 वोट मिले। इसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री भारत भूषण सिंगल 13 मत

पाकर परिषद के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किये गये, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 10 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रपति के चुनाव से असंतुष्ट, प्रतिवादी नंबर 1 ने निम्नलिखित आधारों पर चुनाव याचिका दायर की: -

(i) प्रतिवादी संख्या 3 ने 1978 के नियमों के नियम 71 में निर्धारित प्रक्रिया से पूरी तरह से विचलन किया, जिसमें सदस्यों को टायर मतपत्र में 'हां' या 'नहीं' लिखने के बजाय 'एक्स' का चिह्न लगाने की आवश्यकता थी। ऐसी प्रक्रिया ने मतदान पैटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिसका चुनाव के परिणाम पर वास्तविक प्रभाव पड़ा;

(ii) उस प्रतिवादी संख्या 3 ने एक अलग शीट तैयार की जिसमें सदस्यों के हस्ताक्षर, उनके वार्ड नंबर और उनके नाम शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि शीट पर सदस्यों के नाम और वार्ड नंबर के आगे मतपत्र के सीरियल नंबर भी जोड़ दिए गए। उपस्थित सदस्यों को एहसास हुआ कि उनके मतपत्र संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच के लिए खुले थे क्योंकि वे आसानी से समझ सकते थे कि चुनाव में किसने किसे वोट दिया था। सत्तारूढ़ दल के प्रतिशोध के डर से और यह उजागर होने के खतरे के कारण कि उन्होंने किसे वोट दिया है, सदस्य स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। इससे मतदान के पैटर्न पर असर पड़ा और इस तरह जो मतदान गुप्त तरीके से होना था, वह खुला मामला बन गया।

(6) अपीलकर्ता, जिसे परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बैठक में विधान सभा के स्थानीय सदस्य सहित कुल 32 सदस्य उपस्थित थे, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से 1973 के अधिनियम और नियमों के अनुरूप थी। 1978 का। मतदाता सूची की तैयारी गोपनीयता या दृश्य प्रतिनिधित्व का उल्लंघन नहीं है जिससे किसी मतदाता की पहचान की जा सके। प्रासंगिक समय पर मतदाता सूची की तैयारी पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई. अपीलकर्ता को 13 वोट मिले, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 को 10 वोट मिले। इसी प्रक्रिया के माध्यम से, भारत भूषण सिंगल को 10 वोट हासिल करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। चुनाव के संचालन के समय उनके चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, जिस तरह से चुनाव आयोजित किया गया था उसी के *अनुसार कार्यवाही दर्ज की गई थी* और किसी ने भी गोपनीयता के उल्लंघन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई थी। , उस समय दबाव या अनुचित प्रभाव। चुनाव एक ही दिन में पूरा हो गया. मतपत्र 1978 के नियमों के अनुसार मौके पर तैयार किए गए थे। इस बात से भी इनकार किया गया कि उपस्थित सदस्यों को एहसास हुआ था कि उनके मतपत्र संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच के लिए खुले थे। इस बात से साफ़ इनकार कर दिया गया है कि किसी उम्मीदवार की पहचान की जा सके कि चुनाव में किसने किसे वोट दिया था. आगे बताया गया कि चुनाव हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था। लिखित बयान में यह भी कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी याचिका में स्वीकार किया कि बी जेपी के पास कुल 8 निर्वाचित सदस्य थे और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में,□ उन्हें 10 वोट मिले थे और बी जेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव के मामले में भारत भूषण सिंगल को 13 वोट मिले थे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की स्वयं व्याख्या करते हैं और जैसा कि आरोप लगाया गया है, किसी भी सदस्य पर कोई दबाव नहीं था। याचिका में.

(7) पार्टियों की दलीलों से, निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए

(8) क्या नगर परिषद, पंचकुला के अध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 का चुनाव रद्द किया जा सकता है? ऑप

(2) क्या याचिका वर्तमान में सुनवाई योग्य नहीं है?
ओपीआर

(3) क्या याचिका के पास याचिका दायर करने का कोई *अधिकार नहीं है?* ओपीआर

(4) क्या याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं है? ओपीआर

(5) क्या याचिका झूठे और तुच्छ आधारों पर आधारित है? ओपीआर

(6) क्या याचिकाकर्ता साफ़ हाथों से अदालत में नहीं आया है? ओपीआर

(7) क्या इस न्यायालय को सुनवाई करने और विचारण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है याचिका ? ओपीआर

(8) राहत।"

हालाँकि, कोई भी उचित मुद्दा, जिसे तैयार किया जाना आवश्यक था, तैयार नहीं किया गया है, फिर भी हम इस पहलू में गहराई से विकास नहीं करना चाहते हैं क्योंकि दोनों अदालतें मामले में शामिल वास्तविक विवाद और उसके बाद के सबूतों से अवगत हैं। मामले का फैसला किया.

(9) अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उठाई गई दलीलों को प्रमाणित करने के लिए, वह स्वयं पी डब्ल्यू 1 के रूप में उपस्थित हुए और याचिका में उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया। उनके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि मौके पर तैयार की गई मतदाता सूची एक मोटे लिफाफे में सील कर दी गई थी, जिसे प्रतिवादी नंबर 1 के अनुरोध पर खोला गया और उसे दिखाया गया। इसके बाद इसे दोबारा सील कर दिया गया। क्रॉस के दौरान-□

जांच में उन्होंने स्वीकार किया कि चुनाव की वीडियोग्राफी की गई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सभी वोट वैध पाए गए और कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं किया गया। जब मतपत्रों को गिनती के लिए निकाला गया तो उनका मिलान अंक-सूची से किया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी सदस्य कार्यालय में मौजूद रहे. उन्होंने आगे कहा कि श्री चंद्रमोहन कांग्रेस के हैं. यह सही है कि भाजपा को परिषद में उसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक वोट उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष पद पर मिले। यह सही है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने चुनाव के समय सूचित किया था कि उस उम्मीदवार के नाम के सामने 'X' का निशान लगाया जाना है जिसके पक्ष में मतदाता वोट देना चाहता है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रक्रिया के बारे में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग से शिकायत नहीं की या चुनाव आयोग या उपायुक्त के साथ कोई व्यक्तिगत सम्मेलन नहीं किया या किसी अन्य तरीके से विरोध नहीं किया।

(10) वार्ड नंबर 6 से नगर पार्षद विज ए कुमार कपूर (पी डब्ल्यू 2) ने भी चुनाव याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 के मामले का समर्थन किया। हालांकि, जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में विसंगति के संबंध में कभी कोई पत्राचार नहीं किया। जिसका जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया था. उन्होंने यह भी कहा कि अनपढ़ व्यक्ति भी नगर निगम का चुनाव लड़ सकता है। वह यह नहीं बता सके कि कितने पार्षद साक्षर हैं और कितने निरक्षर। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी और सभी सदस्यों ने एसडीओ (सिविल) के निर्देशानुसार उस व्यक्ति के नाम के आगे कानूनी रूप से 'X* अंकित किया था, जिसके पक्ष में वोट डाले जाने थे।

(11) इसके विपरीत, विजयी उम्मीदवार-अपीलकर्ता ने बीआर धीमान (डीडब्ल्यू1), सचिव, नगर परिषद, पंचकुला से पूछताछ की, जिन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित कार्यवाही Ex.D 1, D2 और D3 के रिकॉर्ड को साबित किया। अध्यक्ष। रविंदर कुमार रावल (DW2) - (अपीलकर्ता) ने अपना हलफनामा Ex.DA प्रस्तुत किया और उससे विस्तार से जिरह की गई। हुडा सचिव (उस समय रिटर्निंग ऑफिसर) के पद पर तैनात एक एचसीएस अधिकारी महेश्वर शर्मा (डीडब्ल्यू 3) ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए नगर परिषद, पंचकुला का चुनाव 14 मई, 2008 को हुआ था और इससे संबंधित कार्यवाही (Ex.D3) रजिस्टर में दर्ज की गई थी। पूरी कार्यवाही संबंधित नियमों के अनुसार की गई और चुनाव प्रक्रिया के बाद पूरा रिकॉर्ड उपायुक्त कार्यालय को सौंप दिया गया।

(12) *जांच* करने पर, चुनाव न्यायाधिकरण ने अपने फैसले दिनांक 4 मई, 2009 (अनुलग्नक पी-2) के तहत मुद्दा संख्या 1 पर निर्णय लेते हुए पाया कि राज्य चुनाव आयोग ने 'एक्स' चिह्न का उपयोग करने के लिए निर्देश जारी किए थे। मतदाता द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार को इंगित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया, इसलिए, 1978 के नियमों के नियम 71 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। प्रतिवादी नंबर 1 और अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष पर कोई क्रॉस-आपत्ति दायर नहीं की गई, - निर्णय दिनांक 8 तारीख के *अनुसार* जून, 2009 (अनुलग्नक पी-4) ने भी निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निष्कर्षों की पुष्टि की:-

> *"याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी) ने इस आधार पर चुनाव के नतीजे पर भी हमला किया है कि एसडीओ (सिविल) ने चुनाव नियमों के नियम 7जे का उल्लंघन किया है, जिसके तहत सदस्यों को मतपत्र में 'हां' या 'नहीं' लिखकर मतदान करना होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के समय। हालाँकि, राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा जारी निर्देशों (दिनांक 17.4.2003) के पूर्व डी4 के अनुसार, सदस्यों को क्रॉस (एक्स) लगाना आवश्यक था।) उस उम्मीदवार के खिलाफ जिसे वह वोट देना चाहता था। इस प्रकार, इस संबंध में एसडीओ (सिविल) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप थी और इसलिए उस आधार पर चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता है। विद्वान न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ उस बिंदु पर एक निष्कर्ष दर्ज किया है और याचिकाकर्ता ने उस निष्कर्ष को चुनौती देते हुए कोई क्रॉस अपील दायर नहीं की है।*

(13) किसी भी तरह, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने फिर से अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया है कि चुनाव, जैसा कि महेश्वर शर्मा (DW3) ने कहा था, राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी दिनांक 17 अप्रैल, 2003 (Ex.D4) के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था। , हरयाणा। 20 जून, 2003 के संशोधित निर्देश निर्देश Ex.D4 का हिस्सा नहीं थे, इसलिए, चुनाव 17 अप्रैल, 2003 के निर्देशों के आधार पर आयोजित किया गया था, जिसमें उस उम्मीदवार के सामने 'X' का निशान लगाने का प्रावधान था, जिसे कोई उम्मीदवार बनाना चाहता था। वोट करें. इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ मामले के इस पहलू को दर्ज किया और अपीलीय प्राधिकारी ने, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर किसी भी क्रॉस-अपील के बिना, फिर से एक निष्कर्ष दर्ज किया कि नियमों के नियम 71 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। 1978 और, इस प्रकार, इस आधार पर चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता है।

(14) इसके विपरीत अपीलकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का खंडन करते हुए प्रतिवादी नंबर 1 के वकील द्वारा मैराथन दलीलें दी गईं। उन्होंने आग्रह किया कि यदि किसी विशेष तरीके से कार्यवाही करने के लिए विशिष्ट नियम बनाए गए हैं, तो ऐसे नियमों का उल्लंघन निश्चित रूप से ऐसे कार्य को शून्य बना देगा। 1978 के नियमों में प्रतिपादित बुनियादी नियम 71 और राज्य चुनाव द्वारा जारी संशोधित निर्देश दिनांक 20 जून, 2003 (अनुलग्नक £ 'ए') के अनुसार, रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को 'X' चिह्न लगाने का निर्देश देने के लिए अधिकृत नहीं था। आयोग, हरियाणा विशेष रूप से मतपत्र पर दर्ज उम्मीदवार के नाम के सामने 'हां' या 'नहीं' अंकित करने का प्रावधान करता है। उन्होंने आगे कहा कि मतपत्र पर क्रम संख्या अंकित करना भी नियमों का उल्लंघन है और यह दृश्यमान प्रतिनिधित्व के बराबर है जिससे गोपनीयता भंग होने की आशंका है। एक बार मतपत्र खुल गया तो सीरियल नंबर से यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि किसने किसे वोट दिया। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना सही था कि मतदाता सूची की तैयारी के साथ-साथ मतपत्रों पर क्रम संख्या अंकित करना गोपनीयता का उल्लंघन है, जिसे चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली भौतिक अनियमितता माना जा सकता है।

(15) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम ऊपर बताए गए अनुसार विवादग्रस्त प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए तैयार हैं।

वह, : प्रश्न संख्या 1

पहले प्रश्न को छूते समय, हम देख सकते हैं कि वोट डालते समय किसी भी मतदाता ने 'X' का निशान लिखने पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उनमें से किसी ने भी 'हाँ' या 'नहीं' का निशान लगाना पसंद नहीं किया। 'X' का निशान लगाने से वोट डालने वाले मतदाताओं पर किसी भी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, हालांकि कभी-कभी छोटे अक्षरों में 'हां' या 'नहीं' का निशान लगाने की स्थिति में मतदाताओं को इस बात का डर हो सकता है कि उन्होंने किसके पक्ष में मतदान किया है। या बड़े अक्षर, और पेन/पेंसिल या स्याही के परिवर्तन से, लेकिन 'X' का निशान बनाकर मतदाताओं की पहचान नहीं की जा सकी। यह विजयी उम्मीदवार की पसंद नहीं थी कि 'X' चिह्न लिखा जाए, बल्कि ऐसा चिह्न रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों के अनुसार लगाया गया था, जिन्होंने 17 अप्रैल, 2003 के निर्देशों का पालन किया था (उदा.D4)) राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया। महेश्वर शर्मा (DW3) को कोई संशोधित निर्देश जारी नहीं किए गए। किसी भी मामले में, यह सर्वविदित है कि एक लोक सेवक/रिटार्मिंग अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्य के लिए

सामान्य प्रक्रिया में और जिस उच्च प्राधिकारी से वह सुसज्जित था, उसके निर्देशों के अनुसार, उसे चुनाव

(4) AIR 1966 Patna 107

आयोग द्वारा ऐसे किसी भी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और दंडित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई हो, तो **मेहला** *बनाम* **रूप राम, (1)** *(पैरा 6)* और **मीरा देवी** *बनाम* **बिहार राज्य चुनाव आयोग और अन्य, (2)** *(पैरा 12 और 13)* के मामले पर भरोसा किया जा सकता है ।

(16) *लिए* अपीलकर्ता के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने **सुदेश कुमार अग्रवाल** *बनाम* **पंजाब राज्य (3)** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया , लेकिन यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है, क्योंकि सुदेश कुमार अग्रवाल के मामले *(सुप्रा) में,* चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि मतदान करने वाले छह सदस्यों ने मतपत्र पर 'हां *' या 'नहीं' लिखने के बजाय 'हां' और ' नहीं' दोनों लिखा था।* हालाँकि, ऐसे वोट अवैध घोषित किये जा सकते थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इन्हें विजयी उम्मीदवार के पक्ष में गिना था। इन तथ्यों पर हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मतदान के तरीके को लेकर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. निश्चित रूप से, 'हाँ *' और 'नहीं'* ' लिखने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि मतदाता को 'हाँ' या 'नहीं* लिखना था, लेकिन तत्काल मामले में केवल 'X' का निशान लगाना था, जिससे मतदाताओं के अधिकारों पर कभी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। . एक भी सदस्य ने अपनी पहचान स्थापित करने/दिखाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अन्य उम्मीदवार के सामने 'X' चिह्न के अलावा कोई अन्य चिह्न नहीं लगाया, जिससे गोपनीयता का उल्लंघन हुआ। इसलिए, मतपत्रों पर 'X' अक्षर से अंकन करना ऐसी कोई बड़ी अनियमितता नहीं कही जा सकती, जिसने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया हो। आगे उल्लेख किया जा सकता है कि सुदेश कुमार अग्रवाल के *मामले (सुप्रा)* में दिए गए फैसले को बाद में 23 अक्टूबर, 2002 **(अशोक कुमार** *बनाम* **सुदेश कुमार अग्रवाल और अन्य) को** दिए गए सिविल अपील नंबर 7054 ऑफ 2001 में शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। **.**

(17) ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम 71 को अनिवार्य मानते हुए नियमों की उचित व्याख्या नहीं की है। कोई वैधानिक प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका प्रकृति का है, यह विधायिका या नियम बनाने वाले प्राधिकारी की मंशा पर निर्भर करता है। कानून या नियम बनाने वाले प्राधिकारी की मंशा को सबसे अच्छी तरह संदर्भ से समझा जा सकता है (1) 1998 (3) पीएलआर 781 (2) एआईआर 2008 पटना 83

(3) 2001 (3) आरसीआर (सिविल) 454

जिसमें विशेष प्रावधान किया गया है। नियम के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान के अभाव में, इसे निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, नियम यह नहीं दर्शाता है कि इसका अनुपालन न करने पर वोट अमान्य हो जाएगा। अत: इसे निर्देशिका मानना होगा। इसी तरह का नियम **बिहारी लैल और अन्य** बनाम **बिंदेश्वरी प्रसाद और अन्य में** व्याख्या के लिए लागू हुआ , (4)। उक्त निर्णय में बिहार राज्य में एक नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शामिल है, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

> *"इन नियमों में से, नियम 6 मतपत्र द्वारा मतदान कराने की विधि निर्धारित करता है। नियम 6 का खंड (बी) इस प्रकार है:*
>
> *(बी) वोट देने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक पार्षद (अध्यक्ष सहित) प्रत्येक पद के लिए उम्मीदवार के नाम के सामने एक क्रॉस चिह्न लगाकर अपना वोट रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ेगा, जिसके लिए वह वोट देना चाहता है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं करेगा, या कोई निशान नहीं बनाएगा। मतपत्र पर और, एक के बाद एक, निर्दिष्ट समय के भीतर इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई मतपेटी में चिह्नित मतपत्र को डालेंगे। यदि कोई पार्षद रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के लिए मतदान करता है, मतपत्र पर हस्ताक्षर करता है या उस पर कोई अन्य निशान बनाता है, तो उसका मतपत्र अवैध माना जाएगा। "*

इसके विपरीत, 1978 के नियमों का नियम 71 इस प्रकार है:-

> "71. मतपत्र लिया जाना और उसका परिणाम-[(1) यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही उम्मीदवार प्रस्तावित है, तो ऐसे उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि प्रत्येक कार्यालय के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान मतपत्र द्वारा होगा। उपस्थित सदस्यों को मतपत्र पर 'हां' या 'नहीं' लिखकर मतदान करना होगा। सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। ऐसे मतदान के लिए विशेष मतपत्र का उपयोग किया जाएगा, प्रत्येक पर उपायुक्त द्वारा लगाया जाने वाला एक आधिकारिक चिह्न होगा।

पटना में प्रचलित नगरपालिका कार्य संचालन (मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव) नियम (1959) के उपरोक्त नियम के आलोक में, यदि तुलना की जाए

1978 के नियमों के नियम 71 के साथ, यह देखा जा सकता है कि नियम 6(बी) अनिवार्य था और इसका स्पष्ट रूप से अनुपालन न करने पर वोट अमान्य हो जाएगा, जबकि, 1978 के नियमों के नियम 71 में ऐसा कोई खंड शामिल नहीं है इसलिए, नियम को निर्देशिका कहा जा सकता है, क्योंकि इस नियम का उल्लंघन मतदान प्रक्रिया को अमान्य नहीं करेगा। साथ ही, यह प्रत्येक तकनीकी उल्लंघन या किसी प्रक्रिया का मामूली उल्लंघन नहीं है, जो अनिवार्य रूप से चुनाव को अमान्य कर सकता है, जब तक कि ऐसे नियम का उल्लंघन चुनाव परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नियमों के निर्माताओं का इरादा यह है कि एक बार होने वाले चुनाव को रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक कि त्रुटि, अवैधता या अनियमितता पर्याप्त चरित्र की न हो जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर रही हो। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने **भूप सिंह** *बनाम* **पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के सचिव और अन्य के माध्यम से मामले में, (5)** प्रक्रिया में मामूली दोष पर चुनाव को रद्द करने के लिए बहुत गंभीर अपवाद लिया, यह देखते हुए कि चुनाव में हर प्रक्रियात्मक प्रावधान कानून को इतना ऊंचा नहीं उठाया जा सकता कि उसका उल्लंघन मतदाताओं के फैसले को *पूरी तरह से पलट दे।* पैराग्राफ 20 में पूर्ण पीठ द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत की गई हैं: -

> "...देश में बुनियादी चुनाव क़ानून, अर्थात् जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का एक मात्र संदर्भ, यह दिखाएगा कि यह केवल भ्रष्ट आचरण, अनुचित अस्वीकृति जैसी मूलभूत कमजोरियों के मामले में है नामांकन पत्रों की कमी, उम्मीदवार में पर्याप्त कानूनी

योग्यता का अभाव या मतदाता सूची में ही बुनियादी त्रुटि, कि चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट है कि ये ऐसे मामले हैं जो या तो चुनाव प्रक्रिया की जड़ तक जाते हैं, या नैतिक अधमता से जुड़े कार्यों के कारण इसकी पवित्रता से जुड़े होते हैं। इसलिए, ऐसे मामलों में, परिणाम पर इसके प्रभाव को प्रभावित किए बिना पूरा चुनाव रद्द कर दिया जाता है। दूसरी ओर, जहां तक किसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने का सवाल है, सिद्धांत यह है कि चुनाव याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। यह न केवल वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन पर लागू होता है, बल्कि देश के सर्वोच्च कानून, अर्थात् संविधान के उल्लंघन पर भी लागू होता है। का प्रतिनिधित्व

---

(8) (2011)2S.C.C. 532

लोके अधिनियम के अलावा, अन्य चुनावी कानूनों का पूरा दांव, जिसका इस स्थान पर विस्तृत संदर्भ अनावश्यक है, मुख्य सिद्धांत को उजागर करेगा कि मतदाताओं के फैसले को हल्के ढंग से अलग रखा जाना चाहिए (विशेष रूप से क़ानून द्वारा निर्धारित मामलों को छोड़कर)) जब तक यह स्पष्ट न हो कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से अत्यधिक कड़े नियम का समर्थन करने के लिए किसी सिद्धांत या मिसाल का हवाला नहीं दिया गया है, जिसे उसकी ओर से प्रचारित किया गया है कि वैधानिक नियम के प्रत्येक पृथक उल्लंघन से पूरे चुनाव को *वास्तव में रद्द कर दिया जाना चाहिए।* मेरा विचार है कि चुनाव कानून में प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान को इतना ऊंचा नहीं उठाया जा सकता कि उसका उल्लंघन मतदाताओं के फैसले को पलट दे? '

हालाँकि, पूर्ण पीठ के उक्त फैसले को एक अलग बिंदु पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन **बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और अन्य (आदि)** *बनाम* **सुरजीत सिंह और अन्य के मामले में उपरोक्त टिप्पणियों को कभी भी खारिज नहीं किया गया था, (6) .**

(17) 1978 के नियमों के नियम 71 में हालांकि 'करेगा' शब्द दर्ज है और कहा गया है कि उपस्थित सदस्यों को मतपत्रों पर 'हां' या 'नहीं' लिखकर मतदान करना होगा, लेकिन नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके। एक अनुमान है कि नियम का अनुपालन न करने पर वोट अमान्य हो जाएगा। अन्यथा भी, इस तरह का नियम सभी वर्गों के पार्षदों पर नहीं लगाया जा सकता है, जिनमें से कुछ ऐसे अंक लिखने में अनपढ़, अंधे या अन्यथा विकलांग हो सकते हैं। **एरा सेझियान** *बनाम* **टीआर बालू और अन्य के** मामले में कानून का समान प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था , (7) जिसमें, यह निम्नानुसार देखा गया था: -

"17. यह महत्वपूर्ण है कि इस उप-नियम में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि वरीयता को उस उद्देश्य के लिए आरक्षित कॉलम में दर्शाया जाना चाहिए, केवल आवश्यकता यह है कि अंक 1 को उम्मीदवार के नाम के सामने लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार, नियम 73 का उप-नियम (2)(बी) केवल यह बताता है कि यदि अंक 1 एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने सेट किया गया है या इस तरह रखा गया है कि यह संदिग्ध हो जाए कि उसने किस उम्मीदवार के लिए आवेदन किया है,

(6) एआईआर 1980 एससी 1612
(7) एआईआर 1990 एससी 838

मतपत्र अवैध होगा. नियम 73 का उप-नियम (2) मतपत्रों की अमान्यता से संबंधित है और उस उप-नियम में यह कहीं नहीं कहा गया है कि केवल गलत कॉलम में वरीयता अंकित होने के कारण, यदि अंकन संबंधित उम्मीदवार के नाम के विपरीत है। मतपत्र अमान्य कर दिया जाएगा. यह सच है कि जिस कॉलम में प्राथमिकता अंकित की जानी चाहिए थी और उस उद्देश्य के लिए अभिप्रेत थी, वह पहले कॉलम के दाईं ओर का कॉलम था जहां उम्मीदवार का नाम डाला जाना था; लेकिन इस आशय का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि जब तक सही कॉलम में प्राथमिकता अंकित नहीं की जाती तब तक मतपत्र अमान्य होगा। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत और एस.एस. में दोहराया गया। **शिवस्वामी** *बनाम* **वी. मलाइकन्नन, (1984) 1 एससीआर104: (एआईआर 1983 एससी 1293),** कि ऐसे मामले में जहां यह सवाल है कि क्या मतपत्र अमान्य है, अदालत का प्राथमिक कार्य मतदाता के इरादे का पता लगाना है। लागू हो जाए। उस मामले में, न्यायालय ने माना कि मतपत्र को अमान्य नहीं माना जाएगा यदि अंकन से एक निश्चित संकेत इकट्ठा करना उचित रूप से संभव हो ताकि उस उम्मीदवार की पहचान की जा सके जिसके पक्ष में वोट देने का इरादा था। यह, निश्चित रूप से, इस नियम के अधीन है कि मतपत्र को वैध मानने से पहले मतपत्र किसी अन्य स्पष्ट प्रावधान के तहत अमान्य नहीं होना चाहिए और मतदाता के इरादे को ऐसे तरीके से व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए जो इसके विपरीत हो। या इसे व्यक्त करने के लिए उक्त अधिनियम या चुनाव नियमों के तहत निर्धारित तरीके से पूरी तरह से असंगत है।"

(18) उपरोक्त निर्णय ने चुनाव संचालन नियम, 1961 (यहां '1961 के नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 56 की व्याख्या विकसित की, जहां परिस्थितियों में मतपत्र को अस्वीकार करने की अनिवार्य शर्त थी। मौजूदा मामले में 2003 के निर्देश (Ex.D4) में कहीं भी ऐसे मतपत्र को खारिज करने का प्रावधान नहीं है। उक्त निर्देशों का खंड 2 (xii) इस प्रकार है:-

"(xii) मतपत्र अमान्य होगा:-

(a) यदि उस पर सदस्य के हस्ताक्षर हैं या उसमें शब्द, या कोई दृश्य प्रतिनिधित्व है जिसके द्वारा उसे पहचाना जा सकता है; या

(b) यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के विरुद्ध अंक दिए गए हों; या

(c) यदि उस पर निशान इस प्रकार लगाया गया है कि यह संदिग्ध हो जाए कि वोट किस एक या दो या अधिक उम्मीदवारों को दिया जाना था।

(d) यदि उस पर कोई चिह्न नहीं लगाया गया है; या

(e) यदि उस पर विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।"

उपरोक्त निर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि किन परिस्थितियों/परिस्थितियों में, निर्धारित प्राधिकारी वोट को अवैध घोषित करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए वे वोट देना चाहते थे, उसके पक्ष में 'एक्स' का निशान लगाने से वोट अवैध नहीं हो जाता, खासकर जब महेश्वर शर्मा (DW3) ने कहा है कि उनके पास राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश (Ex.P4) हैं, जिसमें मतदान के कॉलम में 'X' अंकित करने का प्रावधान है। इस प्रकार, हम नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा की गई टिप्पणियों को बरकरार रखते हैं और इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों से असहमत हैं कि वोट पर टिक मार्किंग इसे अमान्य बना देती है, जिसे उलट दिया गया है। **कल्याण कुमार गोगोई** *बनाम* **आशुतोष अग्निहोत्री और अन्य मामले में, (8)** शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:-

"23. यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और 1961 के चुनाव नियमों के प्रावधानों का अनुपालन उन अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था, जो चुनाव के संचालन के प्रभारी थे, न कि निर्वाचित लोगों द्वारा। उम्मीदवार. यह सच है कि यदि खंड (iv) को अलग से पढ़ा जाता है, तो कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रलोभित हो सकता है कि संविधान के प्रावधानों या 1951 अधिनियम या 1961 के नियमों के किसी भी नियम के अनुपालन में कोई भी गैर-अनुपालन किया गया है। अधिनियम के तहत लौटे हुए उम्मीदवार का चुनाव शून्य हो जाएगा, लेकिन कोई भी इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूल सकता कि खंड (डी) एक शर्त के साथ शुरू होता है, अर्थात्, चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक लौटे उम्मीदवार से संबंधित है, होना चाहिए भौतिक रूप से प्रभावित. इसका मतलब यह है कि यदि यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित नहीं हुआ है कि चुनाव के नतीजे, जहां तक इसका संबंध एक लौटाए गए उम्मीदवार से है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है, का चुनाव□

लौटाया गया उम्मीदवार संविधान या अधिनियम के प्रावधानों या 1961 के नियमों या उसके तहत बनाए गए आदेशों के किसी भी नियम का अनुपालन न करने के बावजूद शून्य घोषित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

दोबारा। : प्रश्न क्रमांक 2.

(19) अब मतदान की गोपनीयता के उल्लंघन के दूसरे प्रश्न पर आते हैं:- 1978 के नियमों के नियम 75 और 85 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह पता चलता है कि चुनाव को रद्द करने के लिए, दो मुख्य आधार हैं- एक 'भ्रष्ट आचरण' और दूसरा अन्य 'भौतिक अनियमितता' है. इस संबंध में 1978 के नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"नियम 75: चुनाव याचिका.—[(1) चुनाव में किसी उम्मीदवार की वापसी के खिलाफ या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की वापसी के खिलाफ या असफल उम्मीदवार के खिलाफ उसकी अयोग्यता की दृष्टि से एक चुनाव याचिका (धारा 272) **[हरियाणा अधिसूचना संख्या जीएसआर 113/एचए24/73/एसएस द्वारा "नियम 87" के स्थान पर प्रतिस्थापित। 257 और 276/82, दिनांक 11 अक्टूबर, 1982]** प्रक्रिया में भ्रष्ट आचरण या भौतिक अनियमितता के आधार पर लिखित रूप में उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार था या एक निर्वाचक, ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत किया जाएगा। उस दिन के बाद तीस दिनों के भीतर जिस दिन चुनाव का परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है **[हरियाणा अधिसूचना संख्या एसओ 72/एचए24/73/एस द्वारा प्रतिस्थापित। 257 और 276/94, दिनांक 19 अगस्त, 1994]।**

बशर्ते कि चौदह दिनों की समय सीमा को उपायुक्त द्वारा बढ़ाया जा सकता है [तीस दिनों से अधिक की अवधि तक] **[हरियाणा अधिसूचना संख्या जीएसआर 113/एचए24/73/एसएस द्वारा डाला गया। 257 और 276/82, दिनांक 11 अक्टूबर, 1982]** यदि उनकी राय में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त आधार हैं। **नियम 85: चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार: (** 1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन, यदि [ट्रिब्यूनल] की राय है, -

(a) क्सक्सक्स क्सक्सक्स क्सक्सक्स

(b) कि नियम 73 के खंड (1), (2), (5) या (6) में निर्दिष्ट कोई भी भ्रष्ट आचरण, निर्वाचित उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार या उसकी सहमति से किया गया है प्रतिनिधि; या

(c) क्सक्सक्स क्सक्सक्स क्सक्सक्स

(d) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक निर्वाचित उम्मीदवार की बात है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है-

(i) क्सक्सक्स क्सक्सक्स क्सक्सक्स

(ii) क्सक्सक्स क्सक्सक्स क्सक्सक्स

(iii) किसी भी वोट को अनुचित तरीके से स्वीकार करने, अस्वीकार करने या अस्वीकार करने या किसी भी वोट को स्वीकार करने से जो शून्य है; या

(iv) चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी भौतिक अनियमितता पर ट्रिब्यूनल निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित कर देगा।

स्पष्टीकरण: - "किसी भी चुनाव की प्रक्रिया में भौतिक अनियमितता" में किसी भी अनुचित स्वीकृति या किसी गैर-सक्रियता या अनुचित स्वागत या वोट से इनकार या किसी भी वोट को स्वीकार करने से इनकार करना शामिल है जो अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के

कारण शून्य है। उसके तहत बनाए गए नियम या उससे जुड़े किसी भी फॉर्म के उपयोग में कोई गलती जो चुनाव के परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

प्रतिवादी नंबर 1 ने चुनाव को रद्द करने के लिए किसी भी भ्रष्ट आचरण को आधार नहीं बनाया है। केवल प्रक्रिया में अनियमितता और गोपनीयता भंग होने के कारण चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई गई है। उपरोक्त उद्धृत दो आधारों में से; पहले आधार के संबंध में, यह पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि निर्वाचक द्वारा केवल 'X' का निशान लगाने से, निर्वाचित उम्मीदवार के परिणाम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इस निष्कर्ष को आगे दर्ज करने में संकोच नहीं करेंगे कि मतदान प्रक्रिया, जो उसी दिन थोड़े समय के भीतर पूरी हो गई थी, प्रक्रिया में ऐसी किसी भी भौतिक अनियमितता का सुझाव नहीं देती है, जिसके गैर-अनुपालन ने चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया है।

(20) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया है कि एकल पीठ ने मतपत्र पर क्रमांक अंकित करने और मतदाता सूची तैयार करने को गोपनीयता का उल्लंघन करार दिया है।

भौतिक अनियमितता, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीयता का अपेक्षित उल्लंघन हो सकता है। ऐसे में इसका असर निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा, लेकिन सिंगल बेंच का रुख सही नहीं था। दरअसल, मतदाता सूची तैयार करने के साथ ही क्रमांक अंकित करना न तो नियम के विरुद्ध था और न ही गोपनीयता का उल्लंघन था।

(21) दूसरे, यह आग्रह किया गया है कि ऐसी कोई दलील नहीं दी गई कि गोपनीयता के कथित उल्लंघन के कारण परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ा। अपने तर्कों को विस्तार से बताते हुए, वह हमें विभिन्न गवाहों के बयानों की ओर ले गए और आग्रह किया कि सबूत ऐसी गोपनीयता के किसी भी उल्लंघन का संकेत नहीं देते हैं। उनका आगे तर्क यह है कि गोपनीयता बनाए रखना लोक सेवकों पर डाला गया दायित्व था और गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में, यह 1973 के अधिनियम की धारा 275 के तहत दंडनीय एक चुनावी अपराध था, जिसमें अधिकतम अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है। मतदान की गोपनीयता भंग होने पर तीन माह या जुर्माना या दोनों।

(22) इसके विपरीत, प्रतिवादी नंबर 1 के वकील ने हमें 1978 के नियमों, 17 अप्रैल, 2003 के निर्देशों (Ex.D4) और राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20 जून, 2003 (अनुलग्नक-ए) से अवगत कराते हुए कहा। हरियाणा ने इस बात पर जोर दिया कि क्रम संख्या अंकित करने या मतदाता सूची तैयार करने से वह सामग्री मिलती है, जहां से "किसने किसे वोट दिया" आसानी से पाया जा सकता है। इस प्रकार, यह एक बड़ी अनियमितता थी, जिसका परिणाम पर गहरा प्रभाव पड़ा।

(23) प्रतिद्वंद्वी दलीलों को गंभीरता से देखने के बाद, हम खुद को अपीलकर्ता के वकील के तर्क से सहमत पाते हैं। तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि मौके पर 35 मतपत्र तैयार किए गए थे, जिन पर सीरियल नंबर अंकित थे और साथ ही काउंटर-फ़ॉइल/इश्यू रसीद भी तैयार की गई थी। सदस्यों को मतदान के लिए ये मतपत्र जारी करने से पहले इनमें फेरबदल किया गया और रसीद पर एक-एक कर उनके हस्ताक्षर लेने के बाद मतपत्र जारी किए गए। महेश वार शर्मा (DW3) ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया दो से तीन घंटे के भीतर पूरी हो गई. इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौके पर तैयार की गई मतदाता सूची को अलग से सील कर दिया गया था और यह बरकरार रही और इसे अदालत द्वारा वी के बयान के अलावा कभी नहीं खोला गया। के. सूद को 27 नवंबर, 2008 को रिकॉर्ड किया गया था और इसे वहीं पर फिर से सील कर दिया गया था। मतदाता सूची तैयार करना और क्रमांक अंकित करना 1978 के नियमों और जारी दिशा-निर्देशों के काफी अनुरूप प्रतीत होता है।

राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा अप्रैल, 20.03 (Ex.D4) में। असल में, चुनाव की प्रकृति चाहे जो भी हो, चुनाव बड़े निर्वाचन क्षेत्र का हो या छोटे निर्वाचन क्षेत्र का; लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नियमों में मतदाता सूची तैयार करने और क्रमांक उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(24) 1961 के नियमों की उप-धारा (2)(एल)(ई) विधानसभा सदस्यों द्वारा चुनाव के संबंध में 'मतदाता सूची' को निम्नानुसार संदर्भित करती है: -

> *(25)* **व्याख्या (एल)(ई)** - विधानसभा सदस्यों द्वारा चुनाव के संबंध में "मतदाता सूची" का अर्थ उस चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा धारा 152 के तहत रखी गई सूची है;"

1961 के नियम 23 में डाक मतपत्र के मामले में एक क्रम संख्या का उल्लेख करने का प्रावधान है और नियम 30 संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान से संबंधित है, और दोनों प्रत्येक मतपत्र से जुड़े काउंटर-फ़ॉइल को संदर्भित करते हैं। इसे और अधिक समझने के लिए, नियम 23 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> *(26) मतपत्र जारी करना- (1) एक डाक मतपत्र डाक द्वारा निर्वाचक को पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत भेजा जाएगा, साथ में-*
>
> *(ए) से (डी) xxx xxx xxx*
>
> *(2)-रिटर्निंग अधिकारी एक ही समय में-*
>
> *(ए) मतपत्र के काउंटरफ़ोइल पर मतदाता की मतदाता सूची संख्या दर्ज करें जैसा कि मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में दर्ज किया गया है।*

(12) AIR 1980 Karnataka 79

इसी प्रकार, चुनाव संचालन और चुनाव याचिका नियम 1951 (यहां '1951 के नियम' के रूप में संदर्भित) का नियम 28 इस प्रकार है: -

> *"किसी चुनाव में मतदान के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मतपत्र, जिस पर यह अध्याय लागू होता है, में एक क्रम संख्या और ऐसे विशिष्ट चिह्न होंगे जो चुनाव आयोग तय कर सकता है।"*

1951 के नियमों का नियम 47(1)(सी) इस प्रकार है:-

> *"मतपेटी में मौजूद मतपत्र को खारिज कर दिया जाएगा यदि उस पर मतदान केंद्र या उस मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए अधिकृत मतपत्रों की क्रम संख्या या निशान से अलग कोई सीरियल नंबर या चिह्न होगा जहां मतपेटी थी। पाया गया प्रयोग किया गया।"*

1978 के नियमों के तहत नगरपालिका चुनावों से संबंधित प्रावधान समान हैं। इन नियमों के नियम 2 का

उप-नियम (के) इन नियमों के तहत नगरपालिका चुनाव में मतदान करने के हकदार व्यक्तियों की मतदाता सूची के रूप में "रोल" को परिभाषित करता है। 1978 के नियमों का नियम 12 नगरपालिका चुनावों के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का प्रावधान करता है। इसके अलावा नियम 36 में प्रावधान है कि "प्रत्येक मतपत्र के साथ एक काउंटर फ़ॉइल जुड़ा होगा, और उक्त मतपत्र और काउंटर-फ़ॉइल ऐसे रूप में होंगे, और उसमें विवरण [हिंदी और ऐसी अन्य भाषा में] होंगे। नियमों के नियम 69(एफ)(4) में प्रावधान है कि "मतपत्रों को क्रमबद्ध तरीके से क्रमांकित किया जाएगा"। नियम 71 उम्मीदवार को जारी किए जाने वाले मतपत्र की प्रकृति को संदर्भित करता है, जो इस प्रकार है:-

"71. ***मतपत्र लिया जाना और उसका परिणाम।-*** [(1) यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही उम्मीदवार प्रस्तावित किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि प्रत्येक कार्यालय के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान मतपत्र द्वारा होगा। उपस्थित सदस्यों को मतपत्र पर 'हां' या 'नहीं' लिखकर मतदान करना होगा। सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। ऐसे मतदान के लिए विशेष मतपत्र का उपयोग किया जाएगा, प्रत्येक पर उपायुक्त द्वारा लगाया जाने वाला एक आधिकारिक चिह्न होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त नियमों की आवश्यकता का पूर्णतः अनुपालन किया गया है। साक्ष्य में आया है कि मौके पर विशेष मतपत्र तैयार किये गये थे. इसलिए, क्रम संख्या के अंकन के संबंध में प्रावधानों को इस नियम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा जारी दिनांक 17 अप्रैल, 2003 (Ex.D4) के निर्देशों का अनुपालन भी किया गया है। . उक्त निर्देशों का खंड (vii) इस प्रकार है:-

"उपायुक्त या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को संदर्भ के अनुसार क्रमांक संख्या निर्दिष्ट करेंगे

उनके नाम *देवनागरी* लिपि में हिंदी में वर्णानुक्रम में लिखे गए और फिर सदस्यों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए क्रम संख्या की घोषणा की गई।

उपरोक्त धारा निर्देशों में उल्लिखित मतपत्रों के फ्रेम के अतिरिक्त है, इसलिए केवल क्रमांक अंकित करना या मतदाता सूची तैयार करना 1978 के नियमों और रिटर्निंग के इस कृत्य का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। अधिकारी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं है। दरअसल, मतपत्र डालने का काम एक अलग डिब्बे में किया जाता है, जहां मतपेटी को इस उद्देश्य के लिए रखा जाता है और जहां मतदान के समय मतदाता के अलावा कोई भी मौजूद नहीं रहता है। यदि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र जारी करने के संबंध में कोई रिकॉर्ड रिकॉर्ड-शीट (फॉर्म 12) में नहीं रखा जाता है, तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं: -

(a) जिस सदस्य को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र जारी किया गया है, वह उसे जेब में रखकर या चबाकर अपना मत नहीं डाल सकता है और ऐसी स्थिति में, ऐसी शरारत करने वाले सदस्य को पहचानना असंभव होगा।

(b) जैसा कि वर्तमान मामले में, जारी किए गए मतपत्रों की संख्या 32 थी, यदि मतपत्रों को जारी करने के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, तो अल्पसंख्यक दल या समूह का कोई भी सदस्य जो अच्छी तरह से जानता था कि उसका/उनका उम्मीदवार यदि संभव हो तो। किसी भी कारण से ढीला हो, मतपेटी में मतपत्र डाले बिना ही वह जेब में जा सकता है और बाद में गिनती के समय मतपेटी से निकाले गए मतपत्रों की संख्या वास्तव में जारी किए गए मतपत्रों से कम पाई जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी यह पहचानने में सक्षम नहीं होंगे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसने शरारत की है।

इस प्रकार, मतपत्र जारी करने का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, लेकिन इसका उपयोग केवल विवाद या गंभीर विवाद की स्थिति में या फर्जी मतदान से बचने के लिए किया जा सकता है। क्रमांक का उल्लेख कोई दृश्य प्रतिनिधित्व नहीं है जिससे किसी निर्वाचक की पहचान की जा सके। इस संबंध में, हम मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं

किमी. श्रद्धा देवी *बनाम* **कृष्ण चंद्र पंत और अन्य, (9)** और **वुडवर्ड** *बनाम* **सारसंस, (10)** जिसमें, यह निम्नानुसार देखा गया था:-

(13) (2009) 7 S.C.C. 115

'यह पीछे की संख्या के अलावा प्रत्येक लेखन या प्रत्येक चिह्न नहीं है जो कागज को अमान्य बनाता है, बल्कि केवल ऐसा लेखन या चिह्न है जिसके द्वारा मतदाता की पहचान की जा सकती है?'

किमी में . **श्रद्धा देवी के मामले** *(सुप्रा) में* इसे इस प्रकार देखा गया:-

"इसका तात्पर्य यह होगा कि निशान और मतदाता की पहचान के बीच कुछ आकस्मिक संबंध होना चाहिए जो एक को देखने पर दूसरे का पता चल जाता है। इसलिए, चिह्न या लेख को ही उचित रूप से मतदाता की पहचान का संकेत देना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे बाहरी साक्ष्य हों जिनसे यह अनुमान लगाया जा सके कि मतदाता द्वारा किसी व्यवस्था के तहत यह निशान लगाया गया है।"

(25) मतदान की गोपनीयता और चुनाव की शुचिता का नियम संविधान में परिकल्पित संसदीय लोकतंत्र की इमारत का समर्थन करने वाले दो केंद्रीय स्तंभ हैं जो एक-दूसरे के साथ टकराव में खड़े हैं या एक-दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (यहां '1951 का अधिनियम' कहा गया है) से सामने आया, राज्य विधानमंडल ने नगरपालिका चुनावों में गोपनीयता के अंतर्निहित उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1973 के अधिनियम की धारा 275 और 275ए के प्रावधानों को स्थापित किया। इन प्रावधानों की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए जिससे संवैधानिक लक्ष्य हासिल करने में मदद मिले। संविधान ने मतदाता पर भरोसा जताया और उससे शहर पर शासन करने के लिए अपना नेता चुनने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की। व्याख्यात्मक प्रक्रिया को लोकतांत्रिक संस्था की स्थापना के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि इसे धीमा करना चाहिए। **रघबीर सिंह गिल** *बनाम* **एस. गुरचरण सिंह टोहरा और अन्य**

(11) के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियाँ की गईं ।

(26) गोपनीयता का अर्थ है बातों को गुप्त रखने का गुण। यह रहस्यों को संदर्भित करता है, जो छिपाना, गोपनीयता और गोपनीयता का पर्याय है, लेकिन "गोपनीयता" शब्द नियमों के गैर-अनुपालन की अनुमति नहीं देता है, लेकिन यह (9) एआईआर 1982 एससी 1569 (10) (1874-75) एलआर 10 सीपी 733 (11) एआईआर 1980 एससी 1362□

इसका तात्पर्य बातों को गुप्त रखना है न कि उसे सार्वजनिक करना। **पाटिल शिवय्या *बनाम* कविशेट्टी शंकरप्पा सुगुरप्पा और अन्य (12)** मामले में दिए गए फैसले में मतपत्र की गोपनीयता और मतदान की गोपनीयता को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है , जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया था: -

> "5. मतदान की गोपनीयता या मतपत्र की गोपनीयता का अर्थ यह तथ्य है कि किसी चुनाव में एक से अधिक प्रतियोगियों में से किसी मतदाता ने अपना वोट किसे दिया है, इसकी जानकारी जनता को नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि अधिनियम की धारा 94 एक मतदाता को यह विशेषाधिकार देती है कि वह उस व्यक्ति की गवाही देने से इनकार कर सके जिसे उसने अपना मत दिया है, और धारा 128 व्यक्तियों को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने से रोकती है। जिन तरीकों से यह जानना संभव है कि किसी व्यक्ति विशेष ने अपना वोट किसे दिया है, वह है मतपेटियों को खोलना और मतपत्रों की जांच करना। अदालतों ने माना है कि मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जो पवित्र है, तुच्छ, अस्पष्ट और अनिश्चित आधार पर मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपरोक्त मामले में, सवाल यह था कि क्या मतदाता सूची को साक्ष्य के रूप में पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि मतदाता सूची का प्रस्तुतीकरण अदृश्य प्रतिनिधित्व और गोपनीयता को लीक करने जैसा नहीं होगा। न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> "6. अब, सवाल यह है कि यदि याचिकाकर्ता को साक्ष्य के रूप में चिह्नित मतदाता सूची को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी जाती है तो क्या मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन होगा? किसी चुनाव में मतदान केंद्रों या मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली चिह्नित मतदाता सूची केवल यह दिखाएगी कि मताधिकार का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा किया गया है या उसके नाम पर जिसका नाम मतदाता सूची में जगह पाता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता। इन मतदाता सूचियों से यह पता लगाना संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति ने वोट डाला है, उसने किसी विशेष उम्मीदवार या प्रतीक को वोट दिया है या नहीं। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को साक्ष्य के रूप में चिह्नित मतदाता सूची को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति देना मतदान की गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। पहला प्रतिवादी भी कोई प्रेरणा नहीं ले सकता□

> यह संबंध नियमों के आर. 93 से है। वह नियम केवल यह प्रावधान करता है कि काउंटरफ़ोइल के साथ अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट, प्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट, प्रयुक्त मतपत्रों के काउंटर-फ़ोइल के पैकेट, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के पैकेट, और के पैकेट। निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाएं और उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन, जबकि ये पैकेट जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की हिरासत में हैं, खोले नहीं जाएंगे और उनकी सामग्री का निरीक्षण या आदेश के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। एक सक्षम न्यायालय।"

(27) **रेखा राणा (एसएमटी)** *बनाम* **जयपाल शर्मा और अन्य (13)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> "24. चिह्नित मतदाता सूची से केवल यह पता लगाना संभव है कि किसी विशेष मतदान केंद्र के मतदाता के नाम पर वोट डाला गया था या नहीं, लेकिन इससे यह समझना कभी संभव नहीं है कि उक्त वोट का लाभार्थी कौन है। मतदाता सूची में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मतदाता ने अपना वोट किसे दिया है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि चिह्नित मतदाता सूची मुख्य रूप से निर्वाचक की पहचान करने के उद्देश्य से रखी जाती है और इस तरह, हम यह देखने में विफल रहते हैं कि इसका उत्पादन "मतपत्र की गोपनीयता" सिद्धांत को कैसे ख़राब करेगा, तदनुसार, हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं इस पहलू पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील।"

(28) फिर, भौतिक अनियमितता के आधार पर चुनाव को रद्द करने का सुनहरा नियम इस तथ्य का प्रमाण है कि निर्वाचित उम्मीदवार का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ होगा। इस मामले में यह घटक गायब है। कुछ नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने मात्र से, जो कि प्रकृति में निर्देशिका भी हैं, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित होगा। पसंद के उम्मीदवार के सामने 'X' अंकित करने का निर्देश रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपने *वास्तविक* आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिया गया था, जो स्पष्ट रूप से राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा (Ex.P4) और आगे से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में था।

इसके अलावा किसी भी मतदाता की ओर से निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया और सभी वोट अधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित तरीके से डाले गए।

(29) हमारे विचार से, किसी भी चुनाव को गोपनीयता के अंदेशे या प्रत्याशित उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। गोपनीयता भंग करने के ऐसे किसी भी कृत्य की वकालत या साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया है। यदि हम अपनी याचिका में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निर्धारित दलीलों पर गौर करें, तो खुलासा करने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्या सूची तैयार करने, मतपत्र जारी करने और मतदान के समय, कोई मतपत्र लीक हुआ था, जिसने प्रभावित किया था , निर्वाचक से प्रभावित, पूर्वाग्रहित होकर उसने जो सोचा था उससे भिन्न तरीके से अपना वोट डाला। कोई भी मतदाता

यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि गोपनीयता भंग होने के कारण ऐसे किसी दबाव के कारण उसे अपना मन बदलना पड़ा या किसी उम्मीदवार ने उसे किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर किया। केवल अस्पष्ट दलीलें हैं कि क्रम संख्या के अंकन के साथ, मतदाताओं को लगा होगा कि उनके मतपत्र जांच के लिए खुले हैं और प्रतिशोध के डर से, उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया होगा। .

(30) अस्पष्ट दलीलों के अलावा, यह भी अच्छी तरह से आकलन किया जा सकता है कि कांग्रेस और भाजपा पार्टी से केवल एक-एक उम्मीदवार ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उन्होंने अपनी पार्टी से एक भी वोट नहीं खोया, बल्कि उप-चुनाव के मामले में- राष्ट्रपति को भी उन्हें पार्टी के वोटों से पांच वोट ज्यादा मिले. ऐसे में, उन्हें यह कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि उनकी पार्टी के वोट किसी भी तरह प्रभावित हुए। वाइन बॉक्स में कोई भी निर्दलीय यह कहने के लिए उपस्थित नहीं हुआ कि उसने किसी धमकी या दबाव के कारण या खुद को होने वाले संभावित नुकसान के मद्देनजर कांग्रेस को वोट दिया है। ऐसे में, ऐसे सबूतों के अभाव में, यह मानना संभव नहीं होगा कि गोपनीयता का कोई उल्लंघन हुआ है। यह भी देखा जा सकता है कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी। यह बात भी सामने आई है कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. उस अवधि के दौरान, कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और न ही किसी प्राधिकारी को संबोधित कोई संचार किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव की कार्यवाही को लिखित रूप में दर्ज किया (Ex.D3) और उस समय, किसी ने भी गोपनीयता के ऐसे किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई। मतपत्रों पर केवल क्रमांक अंकित करने का मतलब ऐसा दृश्य प्रतिनिधित्व नहीं है, जहां से किसी मतदाता को मतदान के लिए उसकी पसंद के संबंध में पहचाना जा सके। □

(31) 1973 के अधिनियम की धारा 275 और 275-ए गोपनीयता बनाए रखने का उल्लेख करती है। अधिनियम 1951 की धारा 128 और 1961 के नियमों के नियम 39 उपरोक्त प्रावधानों के लिए आवश्यक हैं। इन धाराओं में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि चुनाव कराते समय चुनाव में लगे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मतपत्र की गोपनीयता किसी को नहीं बताएंगे (कानून के तहत आवश्यक को छोड़कर) और यदि वे जानबूझकर गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं, तो यह माना जाएगा चुनावी अपराध के रूप में दोनों अधिनियमों के तहत जुर्माना या कारावास से दंडनीय है। मतदान की गोपनीयता या मतपत्र की गोपनीयता का अर्थ यह तथ्य है कि किसी चुनाव में एक निर्वाचक ने एक से अधिक प्रतियोगियों में से किसे अपना वोट दिया है, इसकी जानकारी जनता को नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि अधिनियम की धारा 94 एक मतदाता को यह विशेषाधिकार देती है कि वह यह गवाही देने से इनकार कर सके कि उसने किसे अपना मत डाला है, और धारा 128 व्यक्तियों को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने से रोकती है। इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य से, यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी स्तर या समय पर गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, जो कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली भौतिक अनियमितता थी। किसी भी मामले में, यह प्रतिवादी नंबर 1 का मामला नहीं है जिसने मतपत्र पर क्रमांक संख्या मुद्रित की या उक्त क्रमांक संख्या को मतदाताओं की अलग शीट/रजिस्टर (Ex.D5) पर डालने से "दृश्य प्रतिनिधित्व" होता है। मतदाता की पहचान की जा सकती है और इसलिए, गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है या चुनाव रद्द करने को उचित ठहराया गया है।

(1) 2) अब, अगले बिंदु पर आते हैं कि प्रतिवादी ने न तो भौतिक तथ्यों की वकालत की है और न ही अपने दृष्टिकोण को दबाने के लिए सबूत लाए हैं। 1978 के नियमों का नियम 81(3), जो 1951 के अधिनियम की धारा 83 के प्रावधानों के साथ पैरामटेरिया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 2 का पर्याय है, जो इस प्रकार है:-

> "आदेश VI-2. भौतिक तथ्यों को बताने की दलील देना, साक्ष्य नहीं-' (1) प्रत्येक दलील में केवल उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त रूप में एक बयान शामिल होगा, जिस पर दलील देने वाला पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए, जैसा भी मामला हो, भरोसा करता है, लेकिन वे साक्ष्य नहीं जिनसे उन्हें साबित किया जाना है।
>
> (2) प्रत्येक दलील को, जब आवश्यक हो, पैराग्राफ में विभाजित किया जाएगा, लगातार क्रमांकित किया जाएगा, प्रत्येक आरोप, जहां तक सुविधाजनक हो, एक अलग पैराग्राफ में समाहित किया जाएगा।
>
> (3) दिनांक, योग और संख्याओं को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी अभिव्यक्त किया जाएगा।

अज़हर हुसैन *बनाम* **राजीव गांधी** मामले में , (14) इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

> "याचिका को कार्रवाई के पूरे कारण के साथ कवर करने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और एक भी भौतिक तथ्य को प्रस्तुत करने में विफलता धारा 83 (1) (ए) के आदेश की अवज्ञा होगी। इसलिए, यदि कोई चुनाव याचिका ऐसे किसी दोष से ग्रस्त है तो उसे खारिज किया जा सकता है और अवश्य ही खारिज किया जाना चाहिए।" एक चुनाव याचिका को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है यदि वह सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई का कारण प्रस्तुत नहीं करती है। **राम सरूप** *बनाम* **पीर चंद और अन्य** में , (15) इसे इस प्रकार देखा गया: -
>
> "धारा 83 को अधिनियम की धारा 100 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, आधार को साबित करने के लिए भौतिक तथ्यों को संक्षिप्त तरीके से देना आवश्यक है, हालांकि, आधार को साबित करने के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को बताया जाना चाहिए और यदि ऐसी कोई सामग्री है तथ्य गायब हैं, याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।"

सामंत एन. बालकृष्ण आदि *बनाम* **जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य** में , (16) सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 81, 83 और 86 पर निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> "धारा 83 अनिवार्य है और इसमें चुनाव याचिका को शामिल करना आवश्यक है; पहले भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और फिर यथासंभव पूर्ण विवरण की आवश्यकता होती है। "भौतिक तथ्य" और विवरण के बीच क्या अंतर है? "सामग्री" शब्द से पता चलता है कि कार्रवाई का पूरा कारण तैयार करने के लिए आवश्यक तथ्यों को बताया जाना चाहिए। एक भी भौतिक तथ्य के चूक जाने से कार्रवाई का कारण अधूरा रह जाता है और दावे का विवरण ख़राब हो जाता है। विवरण का कार्य कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जानकारी देना है।

हरि शंकर जैन *बनाम* **सोनिया गांधी, (17)** में यह माना गया था कि 1951 के अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) में कहा गया है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। बताए जाने वाले भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन्हें लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाली सामग्री माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे तथ्य होने चाहिए जो लगाए गए आरोपों का आधार बन सकें (14) एआईआर 1986 एससी 1253 (15) एआईआर 1963 पीबी। एवं हाई. 180 (16) एआईआर 1969 एससी 1201 (17) 2001 (8)एससीसी233

याचिका में और सीपीसी में समझे अनुसार कार्रवाई का कारण बनेगा। अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" को हर उस तथ्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए वादी के लिए साबित करना आवश्यक होगा। एक भी भौतिक तथ्य के चूक जाने से कार्रवाई का कारण अपूर्ण हो जाता है और दावे का विवरण ख़राब हो जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 कानूनी दायित्व के तहत था कि वह उस याचिका की सामग्री के संबंध में आवश्यक अतिरिक्त जानकारी के साथ कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करे, जिसे वह स्थापित करना चाहता था, ताकि अपीलकर्ता को चुनौती के वास्तविक आधारों से अवगत कराया जा सके। केवल अनुभाग के शब्दों को उद्धृत करना भौतिक तथ्यों को बताने के बराबर नहीं है। यदि आवश्यक हो तो भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक कथन और नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक कथन भी शामिल होगा। "भौतिक तथ्यों" को प्रस्तुत करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है। चुनाव कानून पार्टी को निश्चित समय की समाप्ति के बाद भौतिक तथ्यों में संशोधन करने की भी अनुमति नहीं देता है। इस संबंध में, **श्री वेद सिंह** *बनाम* **जितेंद्र सिंह** और अन्य, **(18)** के मामले का संदर्भ लिया जा सकता है ।

(33) इसलिए, कार्रवाई के पूर्ण कारण के अभाव में यह दलील दी गई कि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य नहीं देने से और वह भी यह नहीं बताने से कि याचिकाकर्ता को किसने वोट दिया होगा, चुनाव के नतीजे कैसे प्रभावित हुए हैं गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका या आशंका के परिणामस्वरूप, जिसके आधार पर अपीलकर्ता का चुनाव शून्य था, चुनाव याचिका में कोई विचारणीय मुद्दे का खुलासा नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन/गैर-अनुपालन हो, हालांकि वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक कि ऐसी कोई याचिका दायर करने वाला पक्ष इसे साबित करने में सफल नहीं हो जाता। इसके उल्लंघन के कारण, निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है, निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य नहीं माना जा सकता है। **कल्याण सिंह चौहान** *बनाम* **सीपी जोशी** *(2011 की सिविल अपील संख्या 870 पर 24 जनवरी, 2011 को निर्णय लिया गया)* में शीर्ष अदालत ने चुनाव याचिका पर फैसला सुनाते समय पालन किए जाने वाले कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया: -

> "(1) अदालत के लिए किसी पक्ष को घूम-घूमकर पूछताछ करने की अनुमति देना स्वीकार्य नहीं है। पक्ष को भौतिक तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए और उसे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अदालत उस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ सके।
>
> (18) आईएलआर 200371) पी.बी. एवं हाई. 54
>
> (2) न्यायालय किसी भी ऐसे तथ्य पर विचार नहीं कर सकता जो पक्षों की दलील से परे हो। पार्टियों को उचित दलील देनी होगी और सबूत पेश करके यह स्थापित करना होगा कि एक विशेष अनियमितता/अवैधता से चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।"

उपरोक्त निर्णय में यह विचार व्यक्त किया गया है कि यदि निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए एक भी घोषणा की मांग की जाती है तो ट्रिब्यूनल द्वारा जांच का दायरा केवल इस प्रश्न पर सीमित किया जाना चाहिए कि क्या चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है या नहीं।

(34) कानून, नियमों और प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक रूप से आयोजित चुनाव में मतपत्र के माध्यम से व्यक्त की गई लोगों की इच्छा का गला घोंटने के लिए अत्यधिक तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पर्याप्त ढांचे को परेशान किए बिना नियम का एक मामूली विचलन एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी आधिकारिक कार्य को अवैध नहीं बनाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया शून्य हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार और विकास गतिविधियां रुक जाती हैं, और निर्वाचित मशीनरी रुक जाती है। लाईज में जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार, प्रक्रियात्मक प्रावधानों को थोड़ा-सा भी नजरअंदाज करने से पूरी प्रक्रिया शायद ही शून्य हो सकती है, जब तक कि संविधान के मौलिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो। याचिकाकर्ता (यहाँ प्रतिवादी संख्या 1) ने मतपत्र को स्वीकार करने, किसी विशेष उम्मीदवार के लिए इसका समर्थन करने, उस समय की कार्यवाही को चुनौती दिए बिना और गोपनीयता के ऐसे उल्लंघन को इंगित किए बिना हार स्वीकार कर ली, जो कि भौतिक रूप से हो सकती है। चुनाव के नतीजे को प्रभावित किया, चुनाव को चुनौती दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने मंसूबे में विफल रहे हैं. चुनाव न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायालय दोनों ने मूल मुद्दों को छुआ है और चुनाव परिणाम में गड़बड़ी की है, जबकि यह मानते हुए कि चुनाव के परिणामस्वरूप गोपनीयता का अपेक्षित उल्लंघन हुआ था, इस तरह यह अवैधता की श्रेणी में आता है। लेकिन ट्रिब्यूनल के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि क्या गोपनीयता का उल्लंघन चुनाव को रद्द करने का आधार था और क्या गोपनीयता का कोई उल्लंघन हुआ था और क्या इस संबंध में पर्याप्त दलीलें थीं। इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि ट्रिब्यूनल के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने भी संभावित तरीके से साक्ष्य और कानून की सराहना करने में गलती की है। नतीजतन, निर्णयों (अनुलग्नक पी-2 और पी-4) के माध्यम से उनके द्वारा दिया गया फैसला रद्द किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय ने मर्म को नहीं छुआ है

जो मुद्दे प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं से प्रभावित हैं, जो बहुमत की आवाज को दबाने के लिए शायद ही पर्याप्त हैं। इसलिए, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया है।

(35) परिणामस्वरूप, हम अपील स्वीकार करते हैं, आक्षेपित फैसले को रद्द करते हैं और चुनाव याचिका खारिज करते हैं। लौटाया गया उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में अपना पद फिर से शुरू करने का हकदार माना जाता है क्योंकि उसके लिए पर्याप्त कार्यकाल अभी भी उपलब्ध है।

आर.एम.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा